

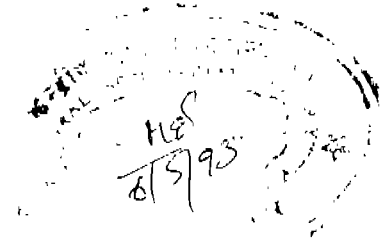


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 96 ]  
No. 96]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 26, 1998/चैत्र 5, 1920  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1998/CHAITRA 5, 1920

भ्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1998

सा.का.नि. 149 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम, 28) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं :—  
इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—  
(क) “अधिनियम” से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम, 28) अभिप्रेत है ।  
(ख) “मुख्य अधिनियम” से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम, 27) अभिप्रेत है ।  
(ग) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ।  
(घ) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं तथा अधिनियम या मुख्य अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें उन अधिनियमों में समनुदिष्ट हैं ।  
(ङ) “विनिर्दिष्ट” से राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है ।  
(च) “उपकर संग्रहक” से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन उपकर के संग्रहण के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ।  
(छ) “निर्धारण अधिकारी” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन उपकर के निर्धारण के लिए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य पदधारण किए हुए हो ।

(ज) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 11 के प्रयोजनार्थ नियुक्त निर्धारण अधिकारी की पंक्ति का कोई ज्येष्ठ अधिकारी।

3. उपकर का उद्ग्रहण :—अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उपकर के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ, सनिर्माण की लागत में नियोजक द्वारा भवन या अन्य सनिर्माण कार्य के सम्बन्ध में उपगत सभी व्यय सम्मिलित होगा किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा—

—भूमि की लागत,

—कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन किसी कर्मकार या उसके किसी संबंधी को संदत्त या संदेय कोई प्रतिकर।

4. संग्रहण का समय और रीति—

(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत उपकर नियोजक द्वारा सनिर्माण परियोजना के पूर्ण होने के तीस दिन के भीतर या उस तारीख से जिसको संदेय उपकर के निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जाता है, से तीस दिन के भीतर, जो भी पहले हो, उपकर संग्रहक को संदत्त किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, जहां परियोजना या सनिर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, जहां उपकर, कार्य के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष पूरा होने के तीस दिन के भीतर संदेय किया जाएगा और तत्पश्चात्, प्रत्येक वर्ष सुसंगत अवधि के दौरान उपगत सनिर्माण की लागत पर अधिसूचित दरों पर संदत्त किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबन्धों के होते हुए भी, जहां उपकर का उद्ग्रहण सरकार या किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के भवन और अन्य सनिर्माण कार्य की बाबत हो जहां ऐसी सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम ऐसे कार्यों के लिए संदेय बिलों में से अधिसूचित दरों पर संदेय उपकर से कटौती करेगी या करवाएगी।

(4) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबन्धों के होते हुए भी, जहां किसी सनिर्माण कार्य के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित हो, जहां ऐसे अनुमोदन के लिए किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन के साथ बोर्ड के पक्ष में सनिर्माण की प्राक्कलित लागत पर अधिसूचित दरों पर संदेय उपकर की रकम का एक क्रासित मांगदेय ड्राफ्ट लगाया जाएगा जो उस स्थान पर संदेय होगा जहां बोर्ड अवस्थित है :

परन्तु यदि परियोजना की अवधि के एक वर्ष से अधिक बढ़ने की संभावना है, जहां मांगदेय ड्राफ्ट प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के दौरान उपगत सनिर्माण की प्राक्कलित लागत पर संदेय उपकर की रकम के लिए होगा और उपकर का शोध्द अतिरिक्त संदाय, उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(5) नियोजक, मुख्य अधिनियम की धारा 46 के अधीन कार्य के प्रारम्भ की सूचना के साथ सनिर्माण की प्राक्कलित लागत के आधार पर संगणित उपकर की रकम, बोर्ड के पक्ष में एक क्रासित मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम रूप से संदाय कर सकता है जो उस स्थान पर संदेय होगा जहां बोर्ड अवस्थित है :

परन्तु यदि परियोजना की अवधि के एक वर्ष से अधिक बढ़ने की संभावना है जहां मांगदेय ड्राफ्ट प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के दौरान उपगत सनिर्माण की प्राक्कलित लागत पर संदेय उपकर की रकम के लिए होगा और उपकर का शोध्द अतिरिक्त संदाय, उपनियम-2 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(6) उपनियम (3), (4) और (5) के अधीन संदत्त अग्रिम उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्तिम निर्धारण में समायोजित किया जाएगा।

5. उपकर के आगमों का बोर्ड को अन्तरण—

(1) नियम 4 के अधीन संग्रहीत उपकर के आगम ऐसे सरकारी कार्यालय, पब्लिक सैक्टर उपक्रम, स्थानीय प्राधिकरण या उपकर संग्रहक द्वारा बोर्ड को, राज्य की लेखन प्रक्रियाओं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के अधीन विहित (और बोर्ड के लेखा शीर्ष में) अन्तरित किया जाएगा।

(2) ऐसे सरकारी कार्यालय या पब्लिक सैक्टर उपक्रम संग्रहीत उपकर से वास्तविक संग्रहण व्ययों का, जो संग्रहीत कुल रकम के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, यथास्थिति, कटौती कर सकेगा या बोर्ड से दावा कर सकेगा।

(3) संग्रहीत रकम, संग्रहण के तीस दिन के भीतर बोर्ड को अन्तरित कर दी जाएगी।

**6. नियोजक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना :**

(1) प्रत्येक नियोजक, यथास्थिति, अपने कार्य के प्रारम्भ होने या उपकर के संदाय के तीस दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी को प्ररूप 1 में सूचना प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में किसी परिवर्तन या उपान्तरण की संसूचना निर्धारण अधिकारी को परिवर्तन या उपान्तरण किए जाने की तारीख के तुरन्त पश्चात्, किन्तु तीस दिन के अपश्चात्, दी जाएगी।

**7. निर्धारण :**

(1) निर्धारण अधिकारी, नियोजक से प्ररूप (1) में सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत की गई सूचना की संवीक्षा करेगा और यदि वह इस प्रकार प्रस्तुत की गई विशिष्टियों की सत्यता के प्रति संतुष्ट है तो वह प्ररूप (1) में ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश करेगा जिसमें नियोजक द्वारा संदेय उपकर की रकम उपदर्शित होगी और उसकी एक-एक प्रति नियोजक, बोर्ड और उपकर संग्रहक को पृष्ठांकित करेगा तथा आदेश को आदेश किए जाने की तारीख से पांच दिन के भीतर प्रेषित करेगा।

(3) यदि प्रस्तुत की गई सूचना की समीक्षा करने पर निर्धारण अधिकारी की यह राय है कि नियोजक ने सनिर्माण की लागत का न्यून संगणन या मिथ्या संगणन किया है अथवा संदेय उपकर की रकम को संगणित किया है तो वह नियोजक को उपकर के निर्धारण के लिए नोटिस जारी करेगा।

(4) ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर नियोजक, नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य की प्रतियों सहित उत्तर प्रस्तुत करेगा :

परन्तु निर्धारक अधिकारी, निर्धारण के दौरान यदि निर्धारिती अपने दावे को सिद्ध करने के लिए सुनवाई का अनुरोध करता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर देगा।

(5) यदि नियोजक उपनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहता है या जहां नियोजक प्ररूप 1 में सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां निर्धारण अधिकारी उपलब्ध अभिलेखों और उससे अनुसंगी अन्य जानकारी के आधार पर निर्धारण प्रारम्भ कर देगा।

(6) निर्धारण अधिकारी कार्य की प्रगति के दौरान किसी भी समय, किसी भी अधिकारी को सनिर्माण की लागत का यथासम्भव सही प्राक्कलन करने के प्रयोजनार्थ कार्य स्थल पर या दस्तावेजी साक्ष्य से अथवा किसी अन्य रीति से, जो वह उचित समझे, जांच करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

**8. अति संदत्त उपकर की वापसी :**

(1) जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश पारित किया है और नियोजक कार्य से हट जाने या उसे पुरोर्बधित करने का विनिश्चय करता है अथवा सनिर्माण योजना को उपान्तरित करता है जिससे हाथ में लिए गए सनिर्माण की लागत कम हो जाती है या अन्य परिस्थितियों के कारण हाथ में लिए गए कार्य की पूर्णता को स्थगित करता है तो वह कार्य में ऐसी कमी या कार्य को रोके जाने का ब्यौरा देते हुए प्ररूप 2 में निर्धारण अधिकारी को सूचना देते हुए निर्धारण आदेश के पुनरीक्षण की मांग कर सकता है।

(2) निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश का पुनरीक्षण प्ररूप 2 में सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उसी प्रकार किया जाएगा जैसे मूल आदेश।

(3) उपनियम (2) के अनुसार निर्धारण के पुनरीक्षण के पश्चात् निर्धारण अधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनरीक्षित निर्धारण में यथा आदेशित अति उपकर के प्रतिदाय के लिए, यथा स्थिति, बोर्ड या उपकर संग्रहक को उसकी एक प्रति पृष्ठांकित करेगा।

(4) बोर्ड, उपनियम (3) के अधीन निर्धारण अधिकारी से पृष्ठांकन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर आदेश में विनिर्दिष्ट रकम का प्रतिदाय नियोजक को मांग देय ड्राफ्ट द्वारा करेगा जो उस स्थान पर संदेय होगा जहां स्थापन अवस्थित है।

(5) जहां अपील प्राधिकारी ने निर्धारण आदेश को उपान्तरित करके उपकर की रकम को कम किया है, वहां प्रतिदाय उस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर किया जाएगा।

**9. छूट :**

(1) किसी राज्य में कोई नियोजक या नियोजकों का वर्ग जो अधिनियम की धारा 6 के अधीन छूट मांगता है, तो महाश्रम कल्याण निदेशक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन करेगा जिसमें हाथ में लिए गए कार्य का ब्यौरा, अधिनियम या उस राज्य में प्रवृत्त तत्समान विधि जिसके अधीन वह सनिर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए उपस्कर का संदाय करने के लिए दायी है, का नाम और वास्तव में संदत्त उपकर की

रकम तथा ऐसे संदाय की तारीख और उसका सबूत का वर्णन कथित करेगा। ऐसे आवेदन की एक प्रति, निर्धारण अधिकारी और संबंधित बोर्ड को पृष्ठांकित की जाएगी।

(2) इस आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे तो संबंधित राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, उक्त आवेदन के आधारों, तथ्यों और गुणावगुणों की परीक्षा करने पर, यथास्थिति, नियोजक या नियोजकों के वर्ग को ऐसे स्थान पर जहां उपकर पहले से उद्ग्रहीत है और ऐसी तत्संबंधी विधि के अधीन संदेय है, अधिनियम के अधीन संदेय उपकर के संदाय से छूट देने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आदेश जारी करेगी।

(4) निर्धारण अधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से प्रारम्भ होकर 30 दिन की अवधि के लिए या उपनियम (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार का आदेश जब तक नियोजक या नियोजकों के वर्ग जिसने उपनियम (1) के अधीन आवेदन किया है तक पहुंचे, जो भी पहले हो, निर्धारण कार्यवाहियां रोक दी जायेंगी।

#### 10. निर्धारण अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियां :

(1) निर्धारण अधिकारी या नियम 7 के उपनियम (8) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसे अधिनियम की धारा (7) के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया हो तो वह—

- (क) ऐसे स्थापन में प्रवेश कर सकेगा जहां भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य चल रहा हो;
- (ख) कार्य स्थल पर पड़ी सामग्री मशीनरी या अन्य वस्तुओं की तालिका बनायेगा;
- (ग) विभिन्न कार्यकलापों में लगे कर्मचारों की संख्या के संबंध में पूछताछ कर सकेगा;
- (घ) किसी विहित रजिस्टर या सन्निर्माण की लागत के निर्धारण का नियोजित कर्मचारों की संख्या से सुसंगत अन्य दस्तावेजों को पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा;
- (ङ) ऐसे किसी अभिलेख की प्रतियां अधिग्रहण कर सकेगा;
- (च) सन्निर्माण कार्य के पूर्ण हुए प्रक्रम का साधारण निर्धारण करेगा;
- (छ) नियोजक या उस स्थान के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति को निदेश दे सकेगा कि किसी सामग्री या मशीनरी को जब तक किसी परीक्षा के लिए उसकी आवश्यकता हो, हटाया नहीं जाएगा या उसमें गड़बड़ नहीं की जायेगी;
- (ज) माप, टिप्पण या फोटोग्राफ लेगा;
- (झ) सन्निर्माण की लागत के युक्तियुक्त निर्धारण के लिए अति आवश्यक समझी जाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

11. उपकर के संदाय की तारीख वह होगी जिसको, यथाशक्ति, नियम-4 के उपनियम (1) के अधीन उपकर संग्रहक के पास रकम जमा की जाती है या नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन स्रोत पर कटौती की जाती है अथवा नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के पास ड्राफ्ट जमा किया जाता है।

#### 12. असंदाय के लिए शास्ति :

(1) निर्धारण अधिकारी को यदि यह प्रतीत होता है कि किसी नियोजक ने निर्धारण आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उपकर संदत्त नहीं किया है या उपकर, इसमें स्रोत पर कटौती किया गया उपकर या अग्रिम रूप से संदत्त उपकर भी है, का कम संदाय किया है तो वह ऐसे नियोजक को नोटिस जारी करेगा कि उसे बकाया समझा जाएगा और ऐसा निर्धारण अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह उचित समझे, ऐसे नियोजक पर उपकर की रकम से अनधिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

परन्तु ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व, ऐसे नियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और यदि ऐसी सुनवाई के पश्चात् निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम किसी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए था, तो ऐसे नियोजक पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

#### 13. अतिशोध्य रकम की वसूली :

असंदत्त उपकर, अतिशोध्य संदाय के लिए ब्याज या इन नियमों के अधीन शास्ति के लेखे शोध्य राशियों की वसूली के प्रयोजनार्थ निर्धारण अधिकारी, शोध्य रकम विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र तैयार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसे सम्बन्धित जिले के कलैक्टर को भेजेगा जो उक्त नियोजक से इसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम ऐसे वसूल करेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

14. अपील (1) ऐसा कोई नियोजक जो नियम 7 के अधीन किए गए किसी निर्धारण आदेश या नियम 12 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसे आदेश की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

- (2) अपील के साथ निम्नलिखित होंगे :
- (क) वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है,
- (ख) उपकर कलक्टर से इस आशय का प्रमाणपत्र कि ऐसी अपील से संबंधित यथास्थिति, उपकर की रकम या शास्ति या दोनों, जमा करा दी गई हैं,
- (ग) ऐसी अपील के अधीन, यथास्थिति, विवाद का शास्ति या दोनों की रकम के एक प्रतिशत के बराबर की फीस,
- (घ) विवाद के मुद्दों का कथन,
- (ङ) दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर निर्भर किया गया है ।
- (3) अपील के प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी, ऐसे अपील के निपटान के लिए यदि वह आवश्यक समझे तो निर्धारण अधिकारी से, उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर आधारित एक विवरण मांग सकेगा ।
- (4) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और अपील का यथा संभव शीघ्र निपटान करेगा ।
- (5) उपकर की मात्रा के प्रति समाधान होने पर अपील प्राधिकारी निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करेगा या यदि उसकी राय में निर्धारण गलत किया गया था या उच्चतर था, तो निर्धारण आदेश को उपान्तरित कर सकेगा या यदि उसकी राय में निर्धारण निम्नतर था या निर्धारण का आधार गलत था तो वह उस निर्धारण आदेश की त्रुटियों को ठीक करने के लिए अपनी टिप्पणी के साथ निर्धारण अधिकारी को वापिस भेजेगा ।
- (6) उपनियम (5) के अधीन किए गए वापसी आदेश का निर्धारण अधिकारी द्वारा निपटान, अपील प्राधिकारी की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए एक मास के भीतर किया जायेगा ।
- परन्तु यदि उपकर की रकम बढ़ाये जाने की प्रस्थापना है तो निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा ।
- (7) इस नियम के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जायेगी ।
- (8) यदि अपील प्राधिकारी की यह राय है कि अधिरोपित शास्ति की मात्रा उच्चतर है या सही नहीं है तो वह, निर्धारण अधिकारी के आदेश को, यथास्थिति उपयुक्त रूप से उपांतरित या अपास्त कर सकेगा ।
- (9) इस नियम के अधीन अपील का निपटान आख्यापक आदेश द्वारा किया जाएगा और ऐसे आदेश की एक प्रति अपीलार्थी, निर्धारण अधिकारी तथा बोर्ड को, ऐसी तारीख से जिसको आदेश किया गया है पांच दिनों के भीतर भेज दी जायेगी ।
- (10) अपील के ऐसे किसी आदेश में जिसमें उपकर की रकम कम की गई हो, बोर्ड से ऐसे अधिक उपकर के प्रतिवाद के लिए भी कहा जायेगा ।
- (11) अपील के किसी ऐसे आदेश में जिसमें शास्ति आवेश में यथास्थिति कमी, बड़ोतरी या उसकी पुष्टि की जा रही हो, वह तारीख भी विनिर्दिष्ट की जायेगी जिस तक शास्ति की रकम का संदाय/प्रतिदाय किया जायेगा ।
- 15. शिकायतों का फाइल करना :** (1) निर्धारण अधिकारी या मुख्य अधिनियम के अधीन किसी निरीक्षक या व्यवसाय संगठन को विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता का उल्लंघन, मिथ्या सूचना दिए जाने, आशय या जानबूझकर उपकर के संदाय का अपवचन करने या अपवचन करने का प्रयास करने की जानकारी मिलती है तो वह बोर्ड को शिकायत कर सकेगा । बोर्ड ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच करेगा और यदि वह ऐसा विनिश्चय करता है तो अपराधी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने के लिए ऐसी शिकायत को केन्द्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।
- (2) केन्द्रीय सरकार ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर, जैसी वह आवश्यक समझे ऐसी जांच कर सकेगी और समुचित अधिकारी क्षेत्र वाले किसी निरीक्षक को न्यायालय में शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

#### प्ररूप-1

(नियम 7 देखिए)

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. स्थापना का नाम | भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) |
|                   | अधिनियम, 1996 के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या                   |
| 2. पता            |   |
| 3. कार्य का नाम   | रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी                                     |

4.	नियोजित कर्मचारों की संख्या				
5.	कार्य-प्रारम्भ की तारीख		कार्य की प्राक्कलित अवधि :		
	तारीख	मास	वर्ष	मास	वर्ष
6.	सनिर्माण की प्राक्कलित लागत		उपकर के संदाय के ब्यौरे		
	प्रक्रम	लागत	रकम चालान सं० अग्रिम-अग स्रोत पर कटौती की तारीख अन्तिम-अग		
	पहला वर्ष				
	दूसरा वर्ष				
	तीसरा वर्ष				
	चौथा वर्ष				
	कुल				
			नियोजक के हस्ताक्षर		
			नियोजक का नाम		
			तारीख		

निर्धारण अधिकारी द्वारा भरा जाएगा

- पूर्ण होने की तारीख
- अन्तिम लगत
- निर्धारण की तारीख
- निर्धारित रकम
- अपील, यदि कोई हो, की तारीख
- निर्धारण प्राधिकारी के आदेश की तारीख
- निर्धारण प्राधिकारी के अनुसार रकम
- बोर्ड को उपकर के अन्तरण की तारीख
- आन्तरिक रकम, चालान सं० और तारीख

हस्ताक्षर

पदाभिधान

#### प्ररूप-II

[नियम 9 देखिए]

- स्थापना का नाम  
पता  
कार्य-प्रारम्भ की तारीख  
तारीख      महीना      वर्ष  
कार्य (मूल) की प्राक्कलित लागत
- भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन)  
अधिनियम, 1996 के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या  
कार्य की प्राक्कलित अवधि :  
महीना      वर्ष  
अग्रिम उपकर/स्टाक पर कटौती  
निर्धारण आदेश की तारीख

## निर्धारित उपकर की रकम

3. मूल प्राक्कलन में उपांतरण पूर्ण होने की पुनरीक्षित तारीख/काम रोके जाने की तारीख/वास्तविक लागत प्राक्कलन उपगत वास्तविक लागत क्या कार्य किसी अन्य व्यक्ति/अधिकरण को पूर्ण किए जाने के लिए सौंपा जा रहा है, यदि हां तो ऐसे व्यक्ति/अधिकरण का नाम/पता

कारण

निर्धारण के पुनरीक्षण की तारीख पुनरीक्षण के पश्चात् उपकर की रकम पहले से प्राप्त उपकर प्रतिदाय किया जाने वाला यदि कोई हो, उपकर

नियोजक के हस्ताक्षर  
निर्धारण अधिकारी के उपयोग के लिए

नियोजक का नाम

तारीख

वसूलनीय उपकर  
बोर्ड के प्रतिदाय के लिए निर्देश,  
तारीख/सं.

हस्ताक्षर

पदनाम

[ फा. सं. एस. 61011/13/96-आर.डब्ल्यू ]

एस. के. दास, महा निदेशक, श्रम कल्याण एवं संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 1998

**GSR/149(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Building and other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (Act 28 of 1996), the Central Government thereby makes the following rules, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) 'Act' means the building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (Act 28 of 1996)
- (b) 'Main Act' means the building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act, 1996 (Act 27 of 1996).
- (c) 'Form' means the form annexed to these rules.
- (d) All other words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Main Act shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.
- (e) 'Specified' means specified by a State Government by an order published in the Official Gazette.
- (f) 'Cess Collector' means an officer appointed by the State Government for collection of cess under the Act.
- (g) 'Assessing Officer' means a gazetted officer of a State Government or an officer of a local authority holding an equivalent post to a gazetted officer of the State Government appointed by such State Government for assessment of Cess under the Act.
- (h) 'Appellate Authority' means an officer, senior in rank to the Assessing Officer, appointed by the State Government for the purposes of section 11 of the Act.

**3. Levy of cess.**—For the purpose of levy of cess under sub-section (1) of section 3 of the Act, cost of construction shall include all expenditure incurred by an employer in connection with the building or other construction work but shall not include—

—cost of land;

—any compensation paid or payable to a worker or his kin under the Workmen's Compensation Act, 1923.

**4. Time and manner of collection.**—(1) The cess levied under sub-section (1) of section 3 of the Act shall be paid by an employer, within thirty days of completion of the construction project or within thirty days of the date on which assessment of cess payable is finalised, whichever, is earlier, to the cess collector.

(2) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1), where the duration of the project or construction work exceeds one year, cess shall be paid within thirty days of completion of one year from the date of commencement of work and every year thereafter at the notified rates on the cost of construction incurred during the relevant period.

(3) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1) and sub-rule (2), where the levy of cess pertains to building and other construction work of a Government or of a Public Sector Undertaking, such Government or the Public Sector Undertaking shall deduct or cause to be deducted the cess payable at the notified rates from the bills paid for such works.

(4) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1) and sub-rule (2), where the approval of a construction work by a local authority is required, every application for such approval shall be accompanied by a crossed demand draft in favour of the Board and payable at the station at which the Board is located for an amount of cess payable at the notified rates on the estimated cost of construction:

Provided that if the duration of the project is likely to exceed one year, the demand draft may be for the amount of cess payable on cost of construction estimated to be incurred during one year from the date of commencement and further payments of cess due shall be made as per the provisions of sub-rule (2).

(5) An employer may pay in advance an amount of cess calculated on the basis of the estimated cost of construction along with the notice of commencement of work under section 46 of the Main Act by a crossed demand draft in favour of the Board and payable at the station at which the Board is located:

Provided that if the duration of the project is likely to exceed one year, the demand draft may be for the amount of cess payable on cost of construction estimated to be incurred during one year from the date of such commencement and further payment of cess due shall be made as per the provisions of sub-rules (2).

(6) Advance cess paid under sub-rules (3), (4) and (5), shall be adjusted in the final assessment made by the Assessing Officer.

**5. Transfer of the proceeds of the cess to the Board.**—(1) The proceeds of the cess collected under rule 4 shall be transferred by such Government office, Public Sector Undertakings, local authority, or cess collector, to the Board alongwith the form of challan prescribed (and in the head of account of the Board) under the accounting procedures of the State, by whatever name they are known.

(2) Such government office or Public Sector Undertaking may deduct from the cess collected, or claim from the Board, as the case may be, actual collection expenses not exceeding one percent of the total amount collected.

(3) The amount collected shall be transferred to the Board within thirty days of its collection.

**6. Information to be furnished by the employer.**—(1) Every employer, within thirty days of commencement of his work of payment of cess, as the case may be, furnish to the Assessing Officer, information in Form, I.

(2) Any change or modification in the information furnished under sub-rule (1) shall be communicated to the Assessing Officer immediately but not later than thirty days from the date of affecting the modification or change.

**7. Assessment.**—(1) The Assessing Officer, on receipt of information in Form I from an employer shall make a scrutiny of such information furnished and, if he is satisfied about the correctness of the particulars so furnished, he shall make an order of assessment within a period not exceeding six months from the date of receipt of such information in Form I, indicating the amount of cess payable by the employer and endorse a copy thereof to the employer, to the Board and to the cess collector and despatch such order within five days of the date on which such order is made.

(2) The order shall inter-alia specify the amount of cess due, cess already paid by the employer or deducted at source and the balance amount payable and the date, consistent with the provision of rule 4, by which the cess shall be paid the cess collector.



(3) If on scrutiny of information furnished, the Assessing Officer is of the opinion that employer has under-calculated or miscalculated the cost of construction or has calculated less amount of cess payable, he shall issue notice to the employer for assessment of the cess.

(4) On receipt of such notice the employer shall furnish to the Assessing Officer a reply together with copies of documentary or other evidence in support of his claim, within fifteen days of the receipt of the notice:

Provided that the Assessing Officer may, in the course of assessment, afford an opportunity to the assessee to be heard in person, if he so requests to substantiate his claim.

(5) If the employer fails to furnish the reply within the period specified under sub-rule (4), or where an employer fails to furnish information in Form I, the Assessing Officer shall proceed to make the assessment on the basis of available records, and other information incidental thereto.

(6) The Assessing Officer may, at anytime while the work is in progress, authorise such officer to make such enquiry at the work site or from documentary evidence or in any other manner as he may think fit for the purpose of estimating the cost of construction as accurately as possible.

**8. Return of overpaid cess.**—(1) Where the Assessing Officer has passed an order of assessment and the employer decides to withdraw from or foreclose the works or modifies the plan of construction thereby reducing the cost of construction undertaken or has been forced by other circumstances to call off the completion of the work undertaken, he may seek revision of the assessment order by making an information in Form II to the Assessing Officer giving details of such reduction or stoppage of work.

(2) Revision of order of assessment shall be made by the Assessing Officer, in the same manner as the original order, within thirty days of receipt of such information in Form II.

(3) Following the revision of assessment as per sub-rule (2), the Assessing Officer shall, wherever necessary, endorse a copy of the revised assessment to the Board or cess collector, as the case may be, for making the refund of excess cess as ordered in the revised assessment.

(4) The Board shall, within thirty days of receipt of the endorsement from the Assessing Officer under sub-rule (3), refund the amount specified in the order to the employer through a demand draft payable at the station where the establishment is located.

(5) Where the Appellate Authority has modified the order of assessment reducing the amount of cess, refund shall be made within such time as may be specified in that order.

**9. Exemption.**—(1) Any employer or class of employers in a state seeking exemption under Section 6 of the Act may make an application to the Director General of Labour Welfare, Ministry of Labour, Government of India, stating the details of works undertaken, name of The Act or corresponding law in force in that State under which he is liable to pay less for the welfare of the construction workers and amount of cess actually paid alongwith the date of such payment and proof thereof. A copy of such application shall be endorsed to each of the Assessing Officer and the board concerned.

(2) On receipt of such application the Central Government may, if it feels necessary, seek a report from the State Government concerned.

(3) On examining the grounds, facts and merits of such application the Central Government may, by notification in the Official Gazette, issue an order exempting the employer or class of employers, as the case may be, from payment of cess payable under the Act where such cess is already levied and payable under such corresponding law.

(4) Assessment proceedings shall be stopped by the Assessing Officer for a period of thirty days commencing from the date of the receipt of a copy of the application under sub-rule (1) to him, or till the order of the Central Government under sub-rule (3) is conveyed to an employer or class of employers who made the application under sub-rule (1), whichever is earlier.

**10. Powers of Assessing Officer and other officers.**—(1) An Assessing Officer, or an officer authorised under sub-rule (8) of Rule 7, if empowered by the State Government under section 7 of the Act, may,—

- (a) enter any establishment where building and other construction work is going on;
- (b) make an inventory of materials, machinery of other articles lying at the work place;

869 CZ/98-2

- (c) enquire about the number of workers engaged in various activities;
- (d) require the production of any prescribed register or any other documents relevant to the assessment of cost of construction or numbers of workers employed;
- (e) seize or take copies of any such records;
- (f) make general assessment of the stage of the construction work having been completed;
- (g) direct the employer or any other person in charge of the place that no material or machinery shall be removed or disturbed for so long as is necessary for the purpose of any examination;
- (h) take measurement, notes or photographs;
- (i) exercise such other powers considered absolutely necessary for reasonable assessment of cost of construction.

**11. Date of payment .—** Of cess shall be the date on which the amount is deposited with the cess collector under sub-rule (1) of rule 4, or the date of deduction at source under sub-rule (3) of rule 4, or the date on which the draft has been deposited with the local authority under sub-rule (4) of rule 4, as the case may be.

**12. Penalty for non-payment.—**(1) An Assessing Officer, if it appears to him that an employer has not paid the cess within the date specified in the assessment order or has paid less cess, including the cess deducted at source or paid in advance, shall issue a notice to such employer that it shall be deemed to be in arrears and such Assessing officer may, after such inquiry as it deems fit, impose on such employer, a penalty not exceeding such amount of cess:

Provided that before imposing any such penalty, such employer shall be given a reasonable opportunity of being heard and if after such hearing the Assessing officer is satisfied that the default was for any good and sufficient reason, no penalty shall be imposed on such employer.

**13. Recovery of overdue amount.—**For the purpose of recovery of sums due on account of unpaid cess, interest for overdue payment or, penalty under these rules, the assessing officer shall prepare a certificate signed by him, specifying the amount due and send it to the collector of the district concerned who shall proceed to recover from the said employer the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue.

**14. Appeal.—**(1) An employer aggrieved by an order of the assessment made under rule 7 or by an order imposing penalty made under rule 12 may appeal against such order, within three months of the receipt of such order, to the Appellate Authority.

(2) The appeal shall be accompanied with—

- (a) the order appealed against;
- (b) a certificate from the cess collector to the effect that the amount of cess or penalty or both, as the case may be, relating to such appeal has been deposited;
- (c) a fee equivalent to one percent of the amount in dispute or penalty or both, as the case may be, under such appeal;
- (d) a statement of points in dispute;
- (e) documentary evidence relied upon.

(3) On receipt of the appeal the Appellate Authority may call from the Assessing Officer a statement on the basis of his assessment order appealed against, as such Appellate Authority may consider necessary for the disposal of such appeal.

(4) The Appellate Authority shall give the appellant an opportunity of being heard in the matter and dispose of the appeal as expeditiously as possible.

(5) On being satisfied on the quantum of cess the Appellate Authority shall confirm the order of the Assessing Officer or if in his opinion the assessment was wrong or on the higher side shall modify the order of assessment or if in his opinion the assessment is on the lower side or if the basis of assessment is wrong, it shall remand back the assessment order to the Assessing officer alongwith his observations to rectify the wrong.

(6) An order remanded back under sub-rule (5) shall be disposed of by the Assessing Officer within one month in view of the observation made by the Appellate Authority:

Provided that if the amount of cess is proposed to be enhanced the assessee shall be given an opportunity of being heard.

(7) No appeal shall lie against the order of the Appellate Authority under this rule.

(8) If the Appellate Authority is of the opinion that the quantum of penalty imposed is on the higher side or not correctly made it shall suitably modify or set aside the order of the Assessing Officer, as the case may be.

(9) The appeal under this rule shall be disposed of by making a speaking order and a copy of such order shall be sent to each of the appellant, the Assessing Officer and the Board within five days of the date on which such order is made.

(10) An order in appeal reducing the amount of cess shall also ask the Board to refund the excess cess.

(11) An order in appeal reducing enhancing or confirming the orders of penalty, as the case may be, shall also specify the date by which the amount of penalty should be paid/refunded.

**15. Filing of Complaints.**— (1) The Assessing Officer, or any inspector under the main Act, or a Trade Union, having come to know of violation of an obligation to furnish return, furnishing of false information, intentionally or willfully evading or attempting to evade the payment of cess may make a complaint to the Board. The Board on receiving such complaint shall examine the complaint and if it so decide may refer such complaint to the Central Government for taking legal action against the offender.

(2) The Central Government on receiving such reference may make such inquiry as may be considered necessary and authorise an inspector of appropriate jurisdiction to file a complaint in the Court of Law.

#### FORM-I

(See rule 7)

1. Name of Establishment	Registration No. under Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.		
2. Address	Registering Authority		
3. Name of Work			
4. No. of Workers employed			
5. Date of commencement of work	Estimated period of work : <u>Month</u>		<u>Year</u>
	Date	Month	Year
6. Estimated cost of construction	Details of payment of cess		
Stages	Cost	Amount Challan No. and date	Advance—A Deduction at Source—D Final—F
1st Year			
2nd Year			
3rd Year			
4th Year			
Total :			

Signature of Employer

Name of Employer

Date

TO BE FILLED BY ASSESSING OFFICER

7. Date of completion

8. Final cost

9. Date of assessment

10. Amount assessed

11. Date of Appeal, if any

12. Date of order in Appeal

13. Amount as per Order in Appeal

14. Date of transfer of cess to the Board

15. Amount transferred Challan No. and date

Signature

Designation

## FORM-II

[See rule 9 (1)]

## NOTICE OF STOPPAGE OR REDUCTION OF WORK

I. Name of Establishment                      Registration No. Under Building and Other Construction Works  
(Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

Address

II. Date of commencement of work              Estimated period of work : Month              Year

Date Month Year

Estimated cost of work (original)

Advance Cess/Deduction at source

Date of Assessment Order

Amount of Cess assessed

III. Modification to the original estimates

Revised date of completion/date of Reason  
stoppage

Actual cost estimates

Actual cost incurred

whether work is being handed over to Yes/No.

any other person/agency for comple-

tion. If yes, Name/Address of such

person/agency.

Signature of employer

Name of employer

Date

## TO BE USED BY ASSESSING OFFICER

Date of revision of assessment

Amount of cess after revision

Cess already received

Cess to be refunded, if any

Cess to be recovered

Reference to Board for refund;

Date/number

Signature

Designation

[File No. S. 61011/13/96-RW]

S.K. DAS, Dy. Genl.

Labour Welfare-cum-Jt. Secy.